

नई दिल्ली। भारत और को छव। सांसदों से कहा कि संसदीय दल की बैठक को संबोधि अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक समझौते ने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था, बल्कि भारतीय संसद के गलियारों में भी नई ऊर्जा भर दी है। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस डील से एक अच्छा आर्थिक माहौल बना है और ग्लोबल ट्रेड वातचीत के प्रति सरकार के स्थिर नजरिए को दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्लगों ने टैरिफ की आलोचना की, प्लेटफॉर्म पर कहा रहा हूं, और आज हम देख रहे हैं कि कौन देशों में ट्रेड टेंशन को बीच में भारत को फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने सांसदों से संसद में पूरी हाजिरी सुनिश्चित करने और चर्चाओं में एक्टिव रूप हिस्सा लेने का भी आग्रह किया और सरकार के काम को जनता

पीएम मोदी की नीतियों से झुकीं महाशक्तियां **मणिपुर में बीजेपी का बड़ा दांव**
अब युमनाम खेमचंद सिंह होंगे नए मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की डेटा साझाकरण प्रथाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह सुनवाई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (बि) के उस आदेश के विरुद्ध दायर अपीलों के एक समूह की सुनवाई के दौरान हुई, जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की स्वीकार करो या छोड़ दो। 4 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (छब-एच) ने बि के जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन नियामक द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को पलटते हुए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डेटा साझाकरण की आशंका अनुमति दी। इसके बाद, 15 दिसंबर, 2025 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसमें अनिवार्य किया गया कि विज्ञापन से संबंधित डेटा साझाकरण जारी रह सकता है, लेकिन सभी प्रकार के डेटा साझाकरण, चाहे वह विज्ञापन से संबंधित हो या गैर-विज्ञापन से, उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट ऑप्ट-आउट अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। पीठ ने ऑप्ट-आउट तंत्रों की प्रभावशीलता पर भी चिंता व्यक्त की, यह देखते हुए कि तमिलनाडु या बिहार के किसी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई सड़क विक्रेता या व्यक्ति गोपनीयता नीतियों में प्रयुक्त च्वालाक भाषा को नहीं समझ सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि उपभोक्ताओं का ब्यावसायिक शोषण और जा रहा है और सौम्य उपभोक्ताओं को आवाजहीन व्यवस्था का शिकार बताया। न्याया ने आगे कहा कि उपयोगकर्ता ऐसे प्लेटफार्मों के आदी हो चुके हैं और वास्तविक विकल्प नहीं हैं कि उन्हें चेतावनी दी थी या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें शर्तों को स्वीकार करने से रक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इस बात पर जोर देते हुए कि निजता के अधिकार से समझ नहीं किया जा सकता, पीठ ने कहा कि वह किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह कि निजता पर चोरी करने का घटिया तरीका है। इस देश में निजता के अधिकार की इतनी रक्षा से रक्षा की जाती है कि हम आसानी से इसका उल्लंघन करने के अनुमति नहीं देंगे। न्यायालय ने अंत में निर्देश जारी करने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई 9 फरवरी 2026 तक कर दी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अखिलेश यादव ने केंद्र को घेरा

अनेक सहयोगियों को जनता के बीच जाकर यह बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ निष्ठावादागत करने के बदले उन्होंने कितना कमीशन लिया है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां न केवल किसानों को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि खाद पदार्थों की बढ़ती कीमतों, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने और अतः किसानों को अपनी जमीन बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर करके निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को भी प्रभावित करेगी। पोस्ट में लिखा था कि इससे न केवल किसान बर्क निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि इससे अनाज और कृषि उत्पादों से मुनाफाखोरी होगी और बिचौलियों की एक नई नस्ल का उदय होगा। परिणामस्वरूप, सभी खाद और पेष पदार्थ और भी महंगे हो जाएंगे। साथ ही, भाजपा इन कंपनियों से चंदा भी वसूलगी, जिससे खाद और कृषि उत्पादों की कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। धीरे-धीरे, इससे हमारे किसानों की खेती

कम हो जाएगी, जिससे जमीन अमीरों और कर्मियों के लिए मजबूर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन भाग्य साधस्यो और हथेयियों का अंतिम लक्ष्य अलावा, समाजवादी पार्टी द राजीव राय ने केंद्र की गोति की आलोचना करते कि इसकी अस्पष्टता में और निर्यतकों को नुकसान है, कारोबारियों के लिए संकट पैदा किया है और मंच पर भारत के राष्ट्रीय कमजोर किया है।

को तारीख घोषित कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार सिपाही भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा 8 जून (सोमवार), 9 जून (मंगलवार) और 10 जून (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा तीनों दिनों में दो-दो पालियों में कराई जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी, परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड एवं दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में प्रदेश में कास्टेबल के कुल 60,244 पदों पर भर्तियां की गई थीं। यह प्रदेश सरकार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी पदों में से 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हुए उम्मीदों नैतिक प्रदान की गई है।

सम्पादक : राजेश शर्मा



के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सेकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह आजला, हिबा इंडन, कुरियाकुरिया, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टेंगार तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने आठों सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374 (2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निर्बाध किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

मणिपुर में बीजेपी का बड़ा दांव
अब युमनाम खेमचंद सिंह होंगे नए मुख्यमंत्री

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में छिपा क्या है?

शशि थरूर ने उठाए सवाल, सरकार से मांगी पूरी पारदर्शिता

को को पूरी पारदर्शिता का चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रम्प कहते हैं कि यह कृत्रिम है, तो भारतीय लोगों के लिए क्या सुरक्षा है? ट्रम्प 500 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा पूरा देश बेल 700 अरब अमेरिकी डॉलर, तो क्या हम अन्य सभी खरीदना बंद कर दें? इससे पहले दिन में, मैं भारत-अमेरिका व्यापार का पूरा विवरण मांगा था। क्षेत्र को खोलने, टैरिफ हटाने और रूसी तेल पर शोध करना जैसे कामों पर सवाल उठाना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया था।

विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लीं, जिस पर सदन में काफी ध्यान गया। दुलारचंद यादव हत्याकांड में तीन महीने से न्यायिक हिरासत में रहे सिंह ने शपथ लेने के बाद बिना ही शपथ ग्रहण समारोह पूरा कर लिया। शपथ लेने के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए, उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने उनसे माथे पर लगे तिलक के बारे में पूछा, जिसके बाद सिंह सदन के सदस्यों की निगाहों के सामने अपनी सीट पर लौट आए। पटना सिविल कोर्ट ने सिंह को केवल शपथ ग्रहण के लिए अनुमति दी थी। जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई है, इसलिए विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होते ही उन्हें ब्यूरो जेल लौटना होगा। सदन में उनकी उपस्थिति संवैधानिक आवश्यकता के कारण ही संभव हो पाई, क्योंकि अनुच्छेद 188 के तहत विधायक को कार्यवाही में भाग लेने के लिए शपथ लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 193 के तहत शपथ के बिना कार्य करना वर्जित है। शपथ लेने के बाद सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे न्याय मिलेगा।

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, 8 से 10 जून तक होगी लिखित परीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। योगीजी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर नवीनीकरण 2025 के तहत की तारीखें घोषित कर दी हैं।

। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार सिपाही भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा 10 जून (सोमवार), 9 जून (मंगलवार) और 10 जून (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा तीनों दिनों में दो-दो पायलों में कराई जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी, परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड एवं दिशा-निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

गल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 में प्रदेश में कांस्टेबल के कुल 60,244 पदों पर भर्तियां की गई थीं। यह प्रदेश सरकार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी पदों में से 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है।

ट्रश्वबेरी की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने वाला' अश्वर्गेनिक बेरी सेफ गार्ड विकसित: डब्ल्यू. मानसी द्विवेदी ने एक ऐसा प्रा. तिक यौगिक तैयार किया है, जिससे सामान्यतः 2-4 दिन में खराब होने वाली स्ट्रश्वबेरी अब सामान्य तापमान पर 12 दिन और कोल्ड स्टोरेज में 25 दिनों तक सुरक्षित रह सकेगी। नवाचार का औद्योगिकरण और पेटेंट : शोध के दौरान विकसित यह इको-फ्रेंडली उत्पाद न केवल पेटेंट...

सिद्धार्थनगर विकास क्षेत्र उसका बाज़ार के ग्राम पंचायत तिधरा निवासिनी मानसी द्विवेदी को दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने वनस्पति विज्ञान में पीएचडी (Doctor of Philosophy) की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने अपना शोध कार्य "Study of Fungal Pathogens causing Strawberry fruit rots and their Management by Natural agents-" विषय पर पूरा किया। यह शोध वनस्पति विज्ञान विभाग की प्रो. पूजा सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। पीएचडी सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि है, जो गहन मौलिक शोध (original research) और थीसिस के सफल बचाव (defence) के बाद विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। यह डिग्री ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता दर्शाती है। इन्होंने अपने शोध में स्ट्रॉबेरी पर कवक संक्रमण तथा इसके प्रा.तिक प्रबंधन का विश्लेषण किया है, इससे सम्बंधित 5 शोध-पत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कोपस इंडेक्स (Q1,Q2, Q3 और Q4) जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। शोध के दौरान इनका पेटेंट प्रकाशित हो चुका था जो अब औद्योगिकरण की ओर अग्रसर है। डॉ. मानसी द्विवेदी ने बताया कि, माननीय कुलपति महोदया प्रो. पूनम टंडन के कुशल नेतृत्व और प्रेरणादायी विजन के कारण विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार का एक उत्कृष्ट वातावरण निर्मित हुआ है, जिसने मुझे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया। निदेशक, अनुसंधान प्रकोष्ठ प्रो. दिनेश यादव, नोडल ऑफिसर डॉ. मनिन्द्र कुमार तथा विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग प्रो.अनिल कुमार द्विवेदी आपके निरंतर सहयोग, दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक सुगमता के लिए आभार व्यक्त किया। आपके मार्गदर्शन ने मेरे शोध दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी है। डॉ. मानसी द्विवेदी ने अपने शोध के दौरान डॉ. रितेश कुमार राय और प्रो. पूजा सिंह के साथ मिलकर श्वर्गेनिक बेरी सेफ गार्डश नामक एक प्रा.तिक यौगिक (Natural Compound) विकसित किया है। यह नवाचार



विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी जैसे शीघ्र खराब होने वाले (Highly Perishable) फलों के लिए वरदान साबित होगा। डॉ. मानसी के शोध विश्लेषण में पाया गया कि यह उत्पाद फलों की शेल्फ लाइफ को अदभुत तरीके से बढ़ा देता है, जो स्ट्रॉबेरी सामान्यत 2-4 दिन में खराब हो जाती है, वह इसके प्रयोग से सामान्य तापमान पर 10-12 दिन और कोल्ड स्टोरेज में 20-25 दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। इसके उपयोग से फलों के स्वाद, पोषण और गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह पूरी तरह प्राकृतिक, इको-फ्रेंडली व सुरक्षित यौगिक है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। कम लागत में तैयार होने के कारण यह किसानों और व्यापारियों के लिए आर्थिक रूप से बेहद किफायती है। डॉ. मानसी द्विवेदी सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार कैलाश नाथ द्विवेदी एवं श्रीमती अर्चना द्विवेदी की सुपुत्री हैं। डॉ. मानसी की इस उपलब्धि पर परिवार, शिक्षकगण और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। स्ट्रॉबेरी की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने वाला' ऑर्गेनिक बेरी सेफ गार्ड विकसित: डॉ. मानसी द्विवेदी ने एक ऐसा प्रा.तिक यौगिक तैयार किया है, जिससे सामान्यतः 2-4 दिन में खराब होने वाली स्ट्रॉबेरी अब सामान्य तापमान पर 12 दिन और कोल्ड स्टोरेज में 25 दिनों तक सुरक्षित रह सकेगी। नवाचार का औद्योगिकरण और पेटेंट : शोध के दौरान विकसित यह इको-फ्रेंडली उत्पाद न केवल पेटेंट, बल्कि औद्योगिक उत्पादन की ओर अग्रसर है। यह तकनीक किसानों और व्यापारियों के लिए कम लागत में फलों को सड़ने से बचाने का किफायती समाधान देगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान : डॉ. मानसी के इस शोध कार्य पर आधारित 5 शोध-पत्र प्रतिष्ठित स्कोपस इंडेक्स (Q1- Q4) जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जो उनके शोध की उच्च गुणवत्ता और वैश्विक मानकों को प्रमाणित करते हैं। लेखक : डॉ. मानसी/ दैनिक बुद्ध का संदेश

सेमीकंडक्टर वाले चिप्स बनाम आलू चिप्स

मध्यम वर्ग का त्याग अब इतना स्थायी हो गया है कि बजट दिवस को 'राष्ट्रीय त्याग दिवस' घोषित कर देना चाहिए। बजट में घोषणा हुई कि हस्तिनापुर का विकास होगा, उसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जायेगा। सुनकर हस्तिनापुर से जुड़ी आत्माएं सक्रिय हुईं।

सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। सरकार का दावा : अर्जुन के रथ जैसी गति मिलेगी। जनता की प्रतिक्रिया : रथ तो तेज होगा, लेकिन किराया इतना होगा कि हम पैदल ही चलना पसंद करेंगे। गरुड़ की गति तो ठीक है, पर जेब में कबूतर की फड़फड़ाहट भी नहीं है?

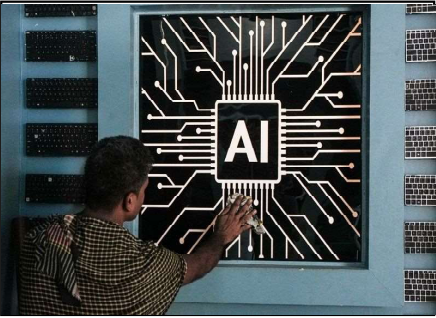
सेमीकंडक्टर और बायो-फार्मा पर हजारों करोड़ का आवंटन। जनता की प्रतिक्रिया रू भविष्य में चिप्स सस्ते होंगे, लेकिन आज आलू के चिप्स ही महंगे हैं। हमारी थाली में आज दाल का भविष्य ही अंधकारमय है। शिक्षा के जरिये रोजगार सृजन की दिशा में कदम महिला छात्रावास का प्रस्ताव सरकार का दावा: द्रौपदी की आत्मनिर्भरता को सम्मान। जनता : अच्छा है, अब कम से कम चौरहरण के समय कोई हॉस्टल वार्डन तो होगा। टैक्स स्लैब जस का तस। सरकार का दावा : मध्यम वर्ग राष्ट्र निर्माण का आधार है। जनता की प्रतिक्रिया : हम कर्ण हैं, लेकिन हर साल कवच-कुंडल उतारते-उतारते अब बनियान भी फट गई है। राहत की जगह हमें 'त्याग का प्रमाणपत्र' मिल रहा है। मध्यम वर्ग का त्याग अब इतना स्थायी हो गया है कि बजट दिवस को 'राष्ट्रीय त्याग दिवस' घोषित कर देना चाहिए। सरकार का दावा रक्षा बजट : देश सुरक्षित रहेगा। जनता : हमारे घर की रक्षा तो प्याज और टमाटर के दाम से ही खतरे में है। असली युद्ध तो रसोई में चल रहा है। बजट : दवाइयां सस्ती होंगी। जनता : कम से कम इलाज में अब डॉक्टर की फीस ही जान लेगी। दवा सस्ती है, लेकिन अस्पताल का बिल अब भी महाभारत का सबसे बड़ा अस्त्र है। बजट में शराब महंगी। सरकार : विदुर की नीति, व्यसन बुरी बात है। जनता की प्रतिक्रिया रू दारू पीने से पहले अब बजट पढ़ना पड़ेगा। विदुर की नीति समझ में नहीं आई, लेकिन जेब खाली हो गई।

बजट के बाद शेयर बाजार गिरा— जनता की प्रतिक्रिया : संजय, ये दृश्य मत दिखाओ, आंखों में आंसू आ रहे हैं। सरकार के बजट का महाभारत एक दिन का होता है, आम जनता का महाभारत तो रोज का है।

शिक्षा के जरिये रोजगार सृजन की दिशा में कदम

यह बजट शिक्षा से रोजगार तक का एकीकृत मार्ग प्रदान करता है। डिजिटल और तकनीकी कौशल को मुख्यधारा में लाता है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था और ऑरेंज इकोनॉमी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाता है। वैश्विक शिक्षा-अनुभव और रोजगार-सृजन के अवसरों को बढ़ाता है। यह बजट केवल आज के युवाओं के लिए नहीं बल्कि अगले पांच दशक के युवाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार कर ...

बजट 2026-27 आने वाले भारत की युवा-आधारित आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें नयी पीढ़ी की शिक्षा, रोजगार, तकनीकी कौशल और रचनात्मक आकांक्षाओं को केंद्र में रखा गया है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर जोर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026दृ 27 को सरकार 'नेक्स्ट जेनरेशन बजट' कह रही है। यह दावा केवल एक राजनीतिक नारा नहीं लगता, बल्कि बजट के प्रावधानों पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि इसमें जेनरेशन जेड-यानी आज के युवा वर्ग- की शिक्षा, रोजगार, तकनीकी कौशल और रचनात्मक आकांक्षाओं को केंद्र में रखा गया है। आज का युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं हैय वह स्किल-ड्रिवन, डिजिटल-नेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बजट 2026-27 इसी बदले हुए युवा चरित्र को पहचानता है। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर जोर। सरकार ने शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक समग्र रणनीति अपनाई है। कौशल-आधारित शिक्षा, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों को बढ़ावा और यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा इस दिशा में अहम कदम हैं।



स्तर पर सही ढंग से लागू होती है तो यह भारत की युवा बेरोजगारी की समस्या को कम करने में निर्णायक साबित हो सकती है। विदेश में पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव चाहने वालों को राहत देने के लिए, सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इससे विद्यार्थी विदेश शिक्षा-अनुभव को अधिक किफायती रूप से चुन सकेंगे, जिससे तकनीकी तथा ग्लोबल मौके और एक्सपोजर मिलेंगे। बजट में ऑरेंज इकोनॉमी यानी एनिमेशन, गेमिंग, डिजाइन, विजुअल इफेक्ट्स

और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देना जेन जेड के लिए एक बड़ा संदेश है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि सरकार अब यूट्यूब, गेमिंग, एनीमेशन और डिजिटल स्टोरीटेलिंग को शौक नहीं, बल्कि कैरियर के रूप में देख रही है। इस कदम का व्यापक लक्ष्य यह है कि भारत 2030 तक लगभग 20 लाख एवीजीसी सेक्टर-विशेषज्ञों की आवश्यकता को पूरा करे, और उसे विश्व-स्तर के डिजिटल क्रिएटिव हब में बदल दे। यह कदम भारत के लाखों क्रिएटिव युवाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट

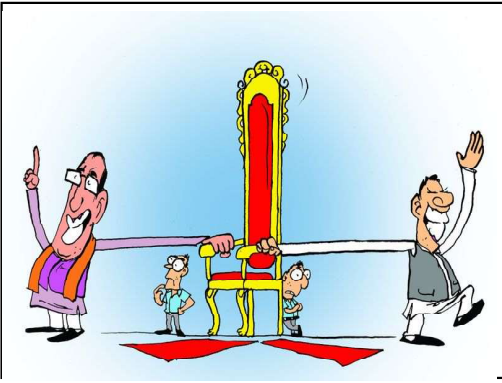
क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग पर दिया गया जोर इस बजट को भविष्य-उन्मुख बनाता है। आज की नौकरियां डेटा, एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम्स से जुड़ी हैं। बजट यह मानता है कि अगर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है, तो युवाओं को इन्हीं क्षेत्रों में दक्ष बनाना होगा। जेन जेड केवल नौकरी चाहने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएटर बनने की आकांक्षा भी रखती है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से नए अवसर पैदा होंगे। इससे युवा उद्यमियों को जोखिम लेने

और नवाचार करने का भरोसा मिलेगा। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)में कमी यह दर्शाती है कि सरकार वैश्विक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर को भी महत्व दे रही है। यह फैसला मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए विशेष रूप से राहतकारी है। भारत का युवा वर्ग पहले से ही स्टार्टअप और नवोन्मेष (इनोवेशन) की ओर अग्रसर है कृयह बजट इन्हें संसाधन-समर्थक वातावरण देने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। बजट ने खेले इंडिया मिशन तथा खेल-इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार से युवाओं के खेल-प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया है। साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र की डिजिटलाइजेशन तथा पर्यटन-संबंधित कौशल विकास योजनाएं भी युवा रोजगार सृजन को आगे बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर, बजट 2026दृ27 केवल आज की जरूरतों का दर्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले भारत की युवा-आधारित आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट जेन जेड को बोझ नहीं, बल्कि भागीदार मानता है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाएं कागज से निकलकर जमीन तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। यदि क्रियान्वयन मजबूत रहा तो यह बजट सचमुच भारत की अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भर, कुशल और ग्लोबल नागरिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

ऐसे मतभेद और टकराव भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वह काफी कुछ वैसा ही कर रही है जैसा कांग्रेस ने दशकों तक किया। हम सैकड़ों साल पुरानी ब्रिटिश परंपराओं पर देश को चलाना चाहते हैं, तो पिछले कुछ दशकों की अपनी परंपराओं पर भी नजर डालनी चाहिए। सच यह है कि जब दो विपरीत राजनीतिक विचारों की सरकारें ...

मान लें कि अभिभाषण की प्रथा समाप्त हो जाए, तब क्या यह विरोध खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानमंडलों से पास विधेयकों को रोककर रखने के प्रकरण का कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। वस्तुतः समस्या संवैधानिक व्यवस्था में नहीं, राजनीतिक संस्कृति में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक विधानसभाओं में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें इस साल भी आई हैं। ऐसा किसी न किसी रूप में पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वर्तमान टकराव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषणों के पढ़ने से जुड़ा है। प्रत्यक्षतः ऐसा अनजाने में नहीं हो रहा है। इन मामलों से जुड़े सभी पक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़ी मर्यादा-रेखाओं से भली भांति परिचित हैं। राज्यपाल जानते-समझते हैं और राज्य सरकारें भी। तब ऐसा क्यों होता है? इन राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपालों के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले राज्यपालों के

'एट होम' कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच सीधा संवाद बहुत कम है। इस वक्त तो चुनाव करीब हैं, इसलिए माहौल में वैसे ही गर्मी भरी है। दक्षिण के जिन तीन राज्यों में विवाद खड़े हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पार्टियों की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के विरोध में हैं। ऐसे विवाद होते ही तभी हैं, जब केंद्र और राज्य की सरकारों का आपसी विरोध हो। बंगाल और पंजाब में भी इससे मिलते-जुलते प्रकरण हुए हैं। राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषणों या विशेष संबोधनों को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है। यह ब्रिटिश परंपरा है, जिस पर आधारित भारत की संसदीय प्रणाली में भी उन्ही परंपराओं के पालन की उम्मीद की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब ब्रिटिश राजा या रानी ने आधि कारिक भाषण को लेकर ना-नुकुर की हो।

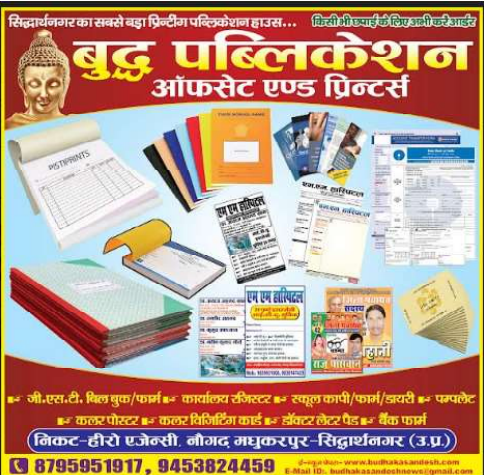


देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बीच बहुत से मामलों में मतभेद थे, पर उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, जिससे संसदीय मर्यादा भंग हो। पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन ने 1998 के गणतंत्र दिवस संबोधन में कुछ बदलाव किया था। कुछ दूसरे मौकों पर भी उन्होंने प्रस्तावित मसौदों में संशोधन किए थे, ताकि भाषण का स्वर और संदेश उनके विचारों के अनुरूप हो।

यह केंद्र-राज्य संबंधों का महत्वपूर्ण पहलू है। सवाल है कि राज्य सरकारों के पास असहमति व्यक्त करने का क्या यही रास्ता बचा है? और क्या राज्यपालों के पास अपने विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार है? सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकारों को संवैधानिक रूप से सीधे राज्यपाल के माध्यम से केंद्र की आलोचना करनी चाहिए? आखिरकार राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त संवैधानिक पद है। उसे

राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, न कि राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। पर क्या केंद्र सरकार को उनके माध्यम से राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए? तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ लगातार टकराव चलने के कारण मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानमंडल के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने का समर्थन किया है। देश के आठवें राष्ट्रपति (1987-1992) आर वेंकटरमण ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधायिका के समक्ष पारंपरिक अभिभाषण की प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश कई बार की थी। वे इस औपनिवेशिक प्रथा को अनावश्यक और असंवेदानिक मानते थे। फरवरी 1988 में संसद में अपना पहला अभिभाषण देने से पहले उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि 'मेरी सरकार' के स्थान पर 'सरकार' शब्द का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा, यह प्रथा ब्रिटिश विरासत का हिस्सा है और भारत में प्रासंगिक नहीं है। भारत का संविधान स्वयं जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया था। ऐसे में देश के राष्ट्रपति द्वारा 'मेरी सरकार' कहना 'अनुचित' है।

इस व्यवस्था को समाप्त करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अनुच्छेद 86 और 175 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास विधायिका को संबोधित करने का अधिकार तब भी बना रहेगा। अतीत में कई राजनेताओं ने राज्यपाल का पद ही खत्म करने का सुझाव दिया है। थोड़ी देर के लिए मान लें कि अभिभाषण की प्रथा समाप्त हो जाए, तब क्या यह विरोध खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्यपालों द्वारा विधानमंडलों से पास विधेयकों को रोककर रखने के प्रकरण का कोई पक्का समाधान नहीं निकला है। वस्तुतः समस्या संवैधानिक व्यवस्था में नहीं, हमारी राजनीतिक-संस्कृति में है।



सिनेमाघरों में जल्द ही भौकाल मचाने पूरी तरह तैयार मिर्जापुर: द फिल्म, मुन्ना-गुइडू की संग छाएगी सचिव जी की दबंगई



और और भी खूनी खेल दर्शकों को देखने को मिल सकता है। बड़े पर्दे पर मिर्जापुर की दुनिया को और ज्यादा रॉ, इंटेंस और सिनेमैटिक तरीके से पेश किए जाने की पूरी तैयारी है।

फिल्म में श्मिर्जापुरख की जान माने जाने वाले किरदार एक बार फिर लौट रहे हैं। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके अलावा इस बार कुछ नए चेहरों की भी एंट्री होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र कुमार (जीतू भैया) और रवि किशन जैसे पॉपुलर स्टार्स भी फिल्म का हिस्सा होंगे, जो कहानी में नए टिविस्ट और तड़का लगाने वाले हैं। मिर्जापुर: द फिल्मख पहले सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी और उसके बाद ही यह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। मेकर्स का प्लान साफ है, पहले थिएटर में भौकाल और फिर ओटीटी पर दोबारा धमाका। यह फिल्म साल 2026 में रिलीज की जाएगी। फिल्म को मिर्जापुर के ओरिजिनल क्रिएटर पुनीत कृष्ण ने लिखा है, जबकि इसका निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है। गौरतलब है कि श्मिर्जापुरख का पहला सीजन 2018 में आया था, दूसरा 2020 में और तीसरा सीजन 2024 में रिलीज हुआ था। तीनों सीजन को दर्शकों से जबरदस्त रिस्रॉन्स मिला। अब जब श्मिर्जापुरख बड़े पर्दे पर आ रही है तो साफ है कि फैंस की निगाहें इसी पर टिकी हैं।

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस: भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार, दूसरे सडे सनी देओल की फिल्म ने मचाया हाहाकार



सनी देओल की वार बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 ने 10 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर धमाका मचा दिया है. फिल्म ने अपने दूसरे सडे की कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. बॉर्डर 2 की आंधी में बीती 30 जनवरी को रिलीज हुई रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दाना 3 उड़ी चुकी है. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 की दसवें दिन की कमाई के बारे में. बॉर्डर 2 ने दसवें दिन भारत में 24.22 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 301.89 करोड़ रुपये हो गया है. सैकनिल्क की मानें तो, सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 अब वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच रही है. फिल्म ने 10 दिनों में ओवरसीज में 45 करोड़ रुपये कमाए हैं और इससे फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 374 करोड़ रुपये हो गया है. हाल ही में, बॉर्डर 2 के हिट होने के दौरान फिल्म के तीसरे पार्ट बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है. फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 की गुडन्यूज फैंस को दी और अब फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, बॉर्डर 2 की बात करें तो इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना का भी कैमियो दिखाया जा रहा है.

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 चल रही कछुआ की चाल, तीसरे दिन हुआ इतना कारोबार



करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है, जो थोड़ा चिंताजनक है।

मर्दानी 3 का ट्रेलर काफी दमदार था जिसे देखकर लोगों ने इसके शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें लगाई थीं। माना जा रहा था कि फिल्म पहले दिन दोहरे आंकड़ों में कमाई करेगी, लेकिन ऐसा न हो सका। वहीं दुनियाभर में, 3 दिनों के अंदर फिल्म की कमाई करीब 25.1 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। तीसरी किस्त से पहले निर्माता 2014 में मर्दानी और 2019 में मर्दानी 2 लेकर आए थे, जिसे खूब सराहा गया था।

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 ने पहले दिन धीमी शुरुआत की, लेकिन इसने हार नहीं मानी। बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चलते हुए इसने तीसरे दिन सबसे ज्यादा कारोबार कर दिखाया है। बता दें, 30 जनवरी को रिलीज मर्दानी 3 के जरिए रानी ने पुलिस अधिकारी शिवाजी शिवाजी रॉय के किरदार में बड़े पर्दे पर दोबारा वापसी की है। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है, जबकि निर्माता यशराज फिल्म्स हैं।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मर्दानी 3 ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन (रविवार) को 7.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो पिछली कमाई के मुकाबले सबसे ज्यादा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 4 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन 6.25 करोड़ कमाते हुए इसने अब तक कुल 17.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। हालांकि, 3 दिनों में फिल्म 20

मेहरीन पीरजादा ने शादी की अफवाहों पर बताई सच्चाई

एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा ने हाल ही में शादी की झूठी खबरों का जोरदार खंडन किया है, और इन बेबुनियाद जानकारियों पर निराशा और गुस्सा जाहिर किया है। एक साफ बयान में, मेहरीन



ने मीडिया से जिम्मेदारी से काम करने की अपील की और जोर देकर कहा कि वह अपनी कोई भी पर्सनल खबर खुद बताएंगी।

लगभग दो सालों तक, मेहरीन ने अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बार-बार उड़ रही अफवाहों के बीच चुप रहना पसंद किया। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में एक अनजान व्यक्ति को उनका पति बताया गया, जिसके बाद उन्हें सामने आकर बोलना पड़ा। उन्होंने साफ किया, मेरी किसी से शादी नहीं हुई है, और इस कहानी को पूरी तरह से झूठा और दुख पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और मीडिया आउटलेट्स से झूठी कहानियाँ बनाना बंद करने को कहा।

मेहरीन ने ऐसी पर्सनल झूठी बातें फैलाने को गलत बताया और फैंस को भरोसा दिलाया कि सही समय आने पर वह अपनी जिंदगी के बारे में अपडेट शेयर करेंगी। उन्होंने कहा, जब मैं शादी करने का फैसला करूंगी, तो मैं खुद दुनिया को बताऊंगी। कृपया मुझ पर भरोसा करें और बिना किसी आधार के अफवाहें फैलाना बंद करें। तेलुगु सिनेमा की उभरती हुई स्टार मेहरीन ने 2016 में नानी के साथ कृष्णा गाडी वीरा प्रेमा गाथा से डेब्यू किया और तुरंत पहचान बनाई। वह एफ2कू फन एंड फ्रस्ट्रेशन, एफ3, पंथम और एंथा मंचिवादायुरा जैसी हिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। मेहरीन ने 2023 की वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ डिजिटल स्पेस में भी कदम रखा। अपने बयान से, मेहरीन को उम्मीद है कि गलत जानकारी फैलने से रुकेगी और उनकी प्राइवसी बनी रहेगी।

लेदर जैकेट को लंबे समय तक नए जैसा रखना है? इस तरह रखें उसका ख्याल



लेदर जैकेट महिलाओं और पुरुषों, दोनों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ये जैकेट ठंड से तो बचाती ही हैं, साथ ही एक स्टाइलिश लुक भी देती हैं। हालांकि, इन जैकेट को सही से रखने और देखभाल करने की जरूरत होती है। ऐसा करने से ये लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार फैशन टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपनी लेदर जैकेट को साफ और नए जैसा रख सकते हैं।

लेदर जैकेट को साफ करने का तरीका

लेदर जैकेट को साफ करने के लिए साबुन का उपयोग न करें, क्योंकि इससे उसका रंग हल्का पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से लेदर उघड़ने का भी डर रहता है। इसके बजाय गीले कपड़े का उपयोग करें और उससे जैकेट को हल्के हाथों से रगड़ें। अगर दाग लगा हो तो एक मुलायम ब्रश का उपयोग करके उसे हल्के हाथों से साफ कर लें। अगर जरूरत पड़े तो लेदर के लिए खासतौर पर बने सफाई वाले उत्पाद उपयोग करें।

ऐसे सुखाएं लेदर जैकेट

लेदर जैकेट को धूप में सुखाना सही नहीं होता है। ऐसा करने से उसका रंग बदल सकता है या वह सिकुड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी लेदर जैकेट को हवा में सुखा लें। अगर बारिश या नमी की वजह से जैकेट गीली हो गई हो तो उसे कमरे के अंदर किसी हवादार जगह पर लटका दें, ताकि वह धीरे-धीरे सूख जाए। इससे जैकेट का आकार और रंग, दोनों ही सुरक्षित रहेंगे।

स्टोर करने का तरीका जानें

लेदर जैकेट को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे उसमें नमी आ सकती है और फफूंद लगने का खतरा रह सकता है। इसके अच्छा होगा कि आप इसे कपड़े के बैग में रखें, जो हवा को आर-पार कर सके। इसके अलावा जैकेट को हमेशा हेंगर पर लटकाएं, ताकि उसका आकार बना रहे और लेदर उघड़े न। कभी भी इसे ढीला न छोड़ें, क्योंकि इससे सिलाई कमजोर होती है और जैकेट खराब हो सकती है।

नियमित देखभाल करें

लेदर जैकेट की नियमित देखभाल करके आप उसे हमेशा नए जैसा रख सकते हैं। हर महीने इसे नम कपड़े से रगड़ें और अगर कोई दाग लगे हों तो उन्हें तुरंत साफ करें। साल में एक बार लेदर के लिए बने विशेष उत्पाद का उपयोग करके उसे साफ करें, ताकि उसकी चमक बरकरार रहे और वह मुलायम बनी रहे। इसके अलावा जैकेट को समय-समय पर पेशेवर रूप से साफ करवाना भी अच्छा होता है, ताकि वह हमेशा नई जैसी दिखे।

फिटिंग का ध्यान रखें

लेदर जैकेट पहनते समय ध्यान रखें कि वह ज्यादा टाइट न हो, क्योंकि इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और आराम भी कम हो सकता है। सही फिटिंग वाली जैकेट चुनें, जो आपके शरीर की आकृति पर अच्छी लगे और आरामदायक हो। इन सरल सुझावों की मदद से आप अपनी लेदर जैकेट को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं और ठंड के मौसम में स्टाइलिश दिख सकते हैं।